sive scheme for studying the cost of cultivation of principal crops are not designed to give separate estimates of cost of production of paddy for the areas specifically mentioned in the question.

There is no direct cultivation of Kayal lands in Kuttanad by the State Government. A portion of Kayamkulam Kayal is being reclaimed and cultivation in the reclaimed land is being carried on by the State Government on an experimental basis. The reclamation work is still in progress.

(b) In order to help the cultivators in Kuttanad, Government are giving pumping subsidy and 50 per cent subsidy on soil ameliorants. In addition, Rs. 60/-per hectare towards cost of pesticides and Rs. 7.50 per hectare towards application charges are provided under the endemic area scheme, resides, a scheme for free supply of pumpsets is also in operation in Kuttanad.

बण सागर के बारे में समझौता

4159. **श्री रमापति सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सोन नदी के जल विवाद को हल करने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य सरकारों के बीच वर्ष 1973 में वण सागर समझौता हुआ था;

(ख) क्या बिहार राज्य को मांग के विरुद्ध केवल 77.50 लाख एकड़ फीट जल का आवंटन किया गया था ;

(ग) क्या वण सागर समझौते के अनुसार जल का उचित बटवारा नहीं हुआ है;

(घ) क्या बिहार राज्य को वण सागर समझौते के अनुसार आवंटित 77.50 लाख एकड़ फीट जल उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित तथा प्रस्तुत योजनाओं की स्वीकृति नहीं दी गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र व्यवस्था करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क)से(ग). सितम्बर, 1973 में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यों के बीच वाणसागर परियोजना और सोन नदी के जल के उपयोग के बारे में एक अंतर्राज्यीय समझौता हुआ था । इस समझौते के अनुसार बिहार को वाणसागर के जल-भंडार में से एक मिलियन एकड़ फुट जल का अधिकार है । यह स्वीकार कर लिया गया कि सोन बेसिन में बिहार की सिंचाई संबंधी आवश्यकताएं 8 मिलियन एकड़ फुट है, जिसमें से 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल सोन नदी से आवंटित किया गया जिसकी 0.25 मिलियन एकड़ फुट तक की अनुपूर्ति गंगा नदी से जल पम्प करके की जा सकती है । बिहार के लिए सोन बसिन में 8 मिलियन एकड़ फुट जल की उपलब्धता पर निर्भर परियोजनाओं को मंजरी देना स्वीकार किया गया ।

(घ) बिहार सरकार ने कुल 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल के समुपयोजन वाली परियोजनाओं की जानकारी दी है । राज्य सरकार से अपनी रिपोर्टों को तदनुसार संशोधित करने का अनुरोध किया गया है ।

(ङ) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है । पांचवीं योजना में बिहार में 14.1 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सजन की परिकल्पना की गई है—4.7 लाख हैक्टेयर बहद और मध्यम स्कीमों से और 9.4 लाख हैक्टेयर लघु स्कीमों से । राज्य सरकार से

अनुरोध किया गया है कि वे सिंचाई विकास को प्राथमिकता प्रदान करें और इस परियोजन के लिए आवश्यक धन राशि और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करें। बिहार को गंडक परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए 1975–76 में 5 करोड़ रुपए के और 1976–77 में 3 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी।

चिरौंजी की सघन खेती

4660. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिरौंजी की सघन खेती की जा सकती है और क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है ;

(ख) क्या चिरौंजी के व्यापारी आदिवासियों से चिरौंजी 5 रुपये अथवा 6 रुपये प्रति किलो खरीद कर 20 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो तक बेचते हैं ; और

(ग) आदिवासियों को उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां श्रीमान। चिरौंजी की सघन खेती करना सम्भव है, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में **बुचनानिया लेटीफोलिया** नामक जंगली पेड़ों से फलों के रूप में इकट्ठा की जाता है। इस सम्बन्ध में अब तक कोई व्यवस्थित अनुसन्धान नहीं की गयी।

(ख) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस मामले को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की जानकारी में लाया जा रहा है जहां चिरौंजी मुख्यत: आदिवासियों और लाइसेंसशुदा ठेकेदारों द्वारा इकट्ठी की जाती है।

Non-lifting of Released Sugar Quota

4661. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that out of 15000 tons of extra sugar quota released last month—9000 tons in U.P. and 1500 tons in Maharashtra were not lifted from the sugar mills at all;

(b) if so, whether the Government are aware that due to non-lifting of this quota—the prices of sugar has not come down as expected; and

(c) what stern steps the Government of India propose to take against the wholesalers who are non-cooperating with the Government and the public?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA):(a) Most of the factories have reported unlifted quantity against the entire quota of 1.20 lakh tonnes of free sale sugar released for the month of June, 1977 (including 15,000 tonnes of additional quantity released on 2-6-1977). Out of the said 1.20 lakh tonnes, 44,427.3 tonnes were released to 73 factories in Uttar Pradesh and 34,215.9 tonnes to 55 factories in Maharashtra. As against this, while 8,004 tonnes of lapse has been reported by the factories in Uttar Pradesh, no lapsed quantity has been reported by the factories in Maharashtra.

(b) The downward trend which the prices of sugar were showing for quite some time was maintained in June, 1977 as also in the current month of July. The wholesale prices of sugar in the five important markets of Delhi, Kanpur, Calcutta, Bombay and Madras were ranging from Rs. 400 to 420 per quintal on 31st May, 1977. The prices further softened and were quoted within the range of Rs. 397/- to